जाति और भारतीय राजनीति

नाम – शीला देवी

राजनीति–विज्ञान

स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसा दीखता था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो रहा है, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त जातिवाद ने फिर जोर पकड़ा और वयस्क मताधिकार व्यवस्था के देश में लागू कर दिए जाने पर राजनीति शक्ति के रूप में उदित हुआ है, राजनीति पर जाति का प्रभाव प्रतिनिधि व्यवस्था के लागू होने के समय से ही शुरू हो गया था, इसके लिए उत्तरदायी है ब्रिटिश प्रशासन। आरम्भ में तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उच्च जातियां ही राजनीति से प्रभावित रही है और राजनीतिक लाभ उन्हीं तक सीमित रहे।

भारत में राजनीति जाति के इर्द–गिर्द घूमती है, जाति प्रमुख दल है। यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया में ऊंचा उठाना चाहता है तो उसे अपनी साथ जाति को लेकर चलना होगा।

जाति एवं प्रशासन :

लोकसभा और विधान सभाओं के लिए, केन्द्र एवं राज्य सरकारों में नौकरियां एवं पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। मैडिकल एवं इन्जीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण के प्रावधान मौजूद है। राष्ट्रीय मोर्चों सरकार ने अगस्त 1990 में मण्डल रिपोर्ट लागू कर नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण 27: का प्रावधान है।

* Granvile, Austin, The Indian Consitution : Corner Stone of a Nation.
* Kashyap Subhash, Dal Badal Aur Rajyon Ki Raneeti.

राज्य राजनीति में जाति :

किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों से अछूती नहीं रही है। बिहार, केरल, तामिलनाडू, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों की राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण के कर ही नहीं सकते। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम यादव, देवी लाल ने भी हरियाणा में जाति की बैसाखियों पर ही सत्ता के शिखर छुने का प्रयास किया।

जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार :

भारत में चुनाव अभियान में प्रत्याशी जिसे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र से जातिवाद की भावना को उकसाया जाता है ताकि प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके। साम्यवादी और मार्क्सवादी दलों ने भी वोट जुटाने के लिए सदैव जाति का सहारा लिया है। 1980 के चुनावों में उत्तर प्रदेश ओर कुछ बिहार के हिस्सों में लोकदल की सफलता पिछड़ी जातियों की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। भारत में जाति का सामाजिक व आर्थिक स्तर जितना निम्न होगा उतना ही उनके मत का अधिक महत्व होगा।

---

* Morris Jons, Government and Politics of India.
* Banerjee, The Draft Constitution of India : A Critique

राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय :

प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनित करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। लोगों की जाति–पाति के प्रति निष्ठा को राजनीतिज्ञ ने थोक वोट के रूप में देखा सत्ता में आने के लिए सदनों में बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से राजनीतिज्ञों ने जाति–पाति के आधार पर उम्मीदवारों के चयन और सत्ता में आने पर उन्हें मंत्रीपद एवं अन्य लाभ के पद उपलब्ध कराए।

निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका :

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गए हैं, जिसके कारण ये जातियां संगठित होकर सरकार पर दबाव डालती है और अन्य जातियां चाहती है कि आरक्षण समाप्त किया जाए।

जातिगत दबाव समूह :

जातिगत दबाव समूह अपने स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति–निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं अनेक जातीय संगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडू में नाजर जाति संघ, गुजरात में क्षत्रिय महासंघ, बिहार में कायस्थ सभा आदि।

---

* Coupland, Constitutional Problem in India.

* Basu, Durga Das, Case on the Constitution of India.

जाति के आधार पर अभिजनों का उदय :

1947 की स्वतन्त्रता ने मध्यम तथा निम्न जातियों के व्यक्तियों को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की अपार सम्भावनाएं प्रदान की। निम्न जातियों के व्यक्तियों के उभरे, आरक्षण नीति के कारण जबकि मध्यम जातियों से अभिजनों का उदय उनके शैक्षिक व सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण तथा 1950 के बाद से राजनीति में प्रतिस्पर्धा के उदय के कारण हुआ।

निष्कर्ष :

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यन्त कठिन कार्य, कई लोग जाति को राजनीति को केन्सर मानते है। जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है, व्यक्तियों में पृथकतावाद की भावना पैदा होती है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को अधिक महत्व देने लगते है। जाति निष्ठाओं का सृजन कर यह प्रथा लोकतन्त्र के विकास मार्ग को अवरूद्व कर देती है।

(शीला देवी)
मकान नं0 1193, सैक्टर–9
करनाल (हरियाणा)